अमेरिका में शिक्षा की भूमि-अनुदान पद्धति

रिक वाउस © ए.पी.-डब्ल्यू.डब्ल्यू.पी.

ऑरेगॉन स्टेट यूनिवर्सिटी में विज्ञान को प्रमुख विषय के रूप में लेकर पढ़ाई करने वाले नेट फ्रांस कॉरवैलिस, ऑरेगॉन में छात्रों द्वारा चलाए जा रहे छोटे से जैविक फार्म में कद्दू के पौधे की देखभाल करते हुए।

अमेरिका में 18 वीं सदी के मध्य से पहले तक सरकारी विश्वविद्यालय नहीं थे, केवल निजी शैक्षिक संस्थाएं थीं। इनमें से किसी भी स्कूल में शिक्षा प्राप्त करना एक औसत अमेरिकी परिवार के लिए काफ़ी महंगा था। वर्ष 1862 में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने मोरिल अधिनियम पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत प्रत्येक राज्य को संघीय सरकार की 10,000 एकड़ भूमि बेच कर उस धन से कृषि तथा तकनीकी शिक्षा के लिए सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया। अधिनियम का नामकरण जस्टिन एस. मोरिल के नाम पर किया गया जो वर्मोंट राज्य के प्रतिनिधि तथा सीनेटर थे और जिन्होंने इसे कानून बनाने का समर्थन किया। मोरिल अधिनियम का उद्देश्य अमेरिका की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसी व्यावहारिक शिक्षा दिलाना था जो उनके जीवन में काम आ सके।

इसके केवल 15 वर्ष बाद ही अमेरिकी कांग्रेस ने कृषि विकास में गहन अनुसंधान की आवश्यकता को महसूस करते हुए 1887 में हैच अधिनियम पर हस्ताक्षर किए। इससे प्रत्येक राज्य को अपने भूमि-अनुदान विश्वविद्यालय से संबद्ध कृषि प्रायोगिक केंद्र की स्थापना के लिए सरकारी आर्थिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार मिल गया। इसके कुछ वर्ष बाद वर्ष 1890 में द्वितीय मोरिल अधिनियम पास हुआ जिसके तहत अमेरिका के अश्वेत बहुल दक्षिणी भाग में भूमि-अनुदान पद्धति से विश्वविद्यालयों की स्थापना का ऐतिहासिक काम संभव हुआ। 1994 में 29 स्थानीय अमेरिकी इंडियन आदिवासी कालेजों को शामिल करके भूमि-अनुदान पद्धति का विस्तार किया गया।

आज सभी 50 राज्यों में भूमि-अनुदान विश्वविद्यालय हैं। इनमें शिक्षा प्रदान करने के साथ ही कृषि से संबंधित अनुसंधान भी किया जाता है। अपने कृषि प्रसार कार्यक्रमों से वे स्थानीय ग्रामीण तथा शहरी लोगों को शिक्षा और अन्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय सलाहकार समितियां शिक्षा की स्थानीय आवश्यकताओं का पता लगाने में मदद करने के साथ ही भूमि-अनुदान विश्वविद्यालयों को उनकी प्राथमिकताओं तथा कार्यक्रमों के लिए सलाह भी देती हैं।

भूमि-अनुदान विश्वविद्यालयों की एक विशेषता यह है कि इन विश्वविद्यालयों को विभिन्न स्रोतों से आर्थिक सहायता मिलती है, जैसे: स्थानीय काउंटी टैक्स, राज्य निधि तथा संघीय सरकार। साथ ही उन्हें शिक्षा तथा अनुसंधान के लिए व्यापारिक संस्थाओं, उद्योगों तथा निजी प्रतिष्ठानों से भी काफ़ी सहायता मिलती है।

आज अमेरिका के भूमि-अनुदान विश्वविद्यालय कृषि के अलावा कई अन्य पाठ्यक्रम भी चला रहे हैं, लेकिन अन्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की तुलना में उनका मूल मिशन अब भी बिल्कुल स्पष्ट है: कक्षाओं में शैक्षिक अध्यापन, प्रसार कार्यक्रमों के माध्यम से अनौपचारिक अथवा अनवरत शिक्षा और प्रायोगिक केंद्रों तथा विश्वविद्यालय के अन्य केंद्रों में अनुसंधान। अमेरिका के भूमि-अनुसंधान विश्वविद्यालयों ने खुलापन, आसान पहुंच और लोगों तथा विभिन्न समुदायों की सेवा के अपने मूल लोकतांत्रिक अधिकार को बनाए रखा है। इनमें से अनेक विश्वविद्यालय आज अमेरिका की अत्यधिक प्रतिष्ठित सरकारी अनुसंधान संस्थाएं बन गई हैं।

अमेरिका के भूमि-अनुदान विश्वविद्यालयों ने 1960 के दशक की भारत की हरित क्रांति में सहायता की। उस समय स्थापित कई राज्य कृषि विश्वविद्यालय जैसे पंजाब कृषि विश्वविद्यालय अमेरिकी तर्ज़ पर शुरू किए गए।

अमेरिकी भूमि-अनुदान विश्वविद्यालयों ने विगत 50 वर्षों के दौरान अंतरराष्ट्रीय कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई है। भूमि-अनुदान संस्थाओं को यू.एस. एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डवलपमेंट (यूएसएड) के साथ उच्च शिक्षा तथा निजी क्षेत्र के उद्यमों के माध्यम से अमेरिका में सहभागिता विकसित करने के लिए आमंत्रित किया गया ताकि विदेशों में कार्यक्रम लागू किए जा सकें।

अमेरिका के भूमि-अनुदान विश्वविद्यालयों ने 1960 के दशक में हरित क्रांति के दौरान भारत की मदद की और उस अवधि में राज्यों में जो कृषि विश्वविद्यालय खोले गए, जैसे पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, उन्हें अमेरिका की भू-अनुदान पद्धति पर ही ढाला गया। आज भारत-अमेरिकी कृषि ज्ञान पहल के तहत भूमि-अनुदान विश्वविद्यालय सक्रिय रूप से भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग कर रहे हैं।

भूमि-अनुदान विश्वविद्यालय पद्धति में लगातार निवेश के कारण अमेरिका में कृषि क्षेत्र को काफ़ी सफलता मिली है। अमेरिकी भूमि-अनुदान विश्वविद्यालयों और भारतीय संस्थाओं की सहभागिता से दोनों को विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा विशेषज्ञता का भरपूर लाभ मिला है। कृषि के क्षेत्र में अमेरिका और भारत के बीच निरंतर सहयोग से ऐसे संबंध और भी फूलेंगे-फलेंगे। **-डै. मि.**

भारत में सक्रिय अमेरिकी भूमि-अनुदान विश्वविद्यालय

ऑबर्न यूनिवर्सिटी

कॉर्नेल यूनिवर्सिटी
तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय; कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़, कर्नाटक; आचार्य एन. जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद से संबद्ध और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ कार्यरत।

ऑयवा स्टेट यूनिवर्सिटी
कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बेंगलूर से संबद्ध

कैन्सस स्टेट यूनिवर्सिटी

मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी
महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड तथा तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के साथ सहभागिता।
नॉर्थ कैरोलाइना एग्रीकल्चर एंड टेक्निकल स्टेट यूनिवर्सिटी

ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय से संबद्ध

पेंसिल्वैनिया स्टेट यूनिवर्सिटी
तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के साथ कार्यरत।

पर्ड्यू यूनिवर्सिटी
कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बेंगलूर से संबद्ध

टेक्सस ए एंड एम यूनिवर्सिटी

टक्सेजी यूनिवर्सिटी
आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद के साथ कार्यरत।

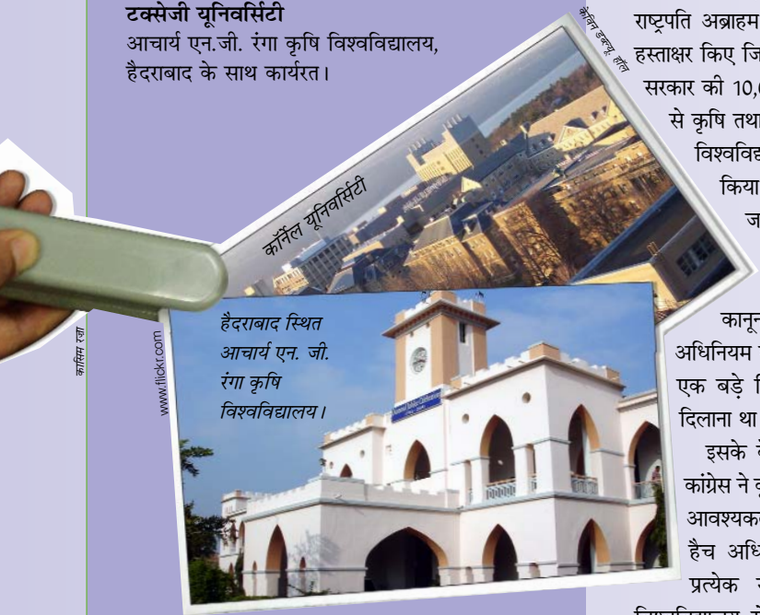

कॉर्नेल डब्ल्यू. हॉल

कासिम रज़ा

यूनिवर्सिटी ऑफ़ कैलिफ़ोर्निया-डेविस
तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय से संबद्ध

यूनिवर्सिटी ऑफ़ फ्लोरिडा
यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय-शैंपेन/अर्बाना
हिंदुस्तान लीवर, ब्रिटानिया, महिंद्रा के साथ सहभागिता

वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी
तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ कार्यरत।